

हाथरस में रोजाना बदल रहा मौसम तापमान में आई गिरावट, तेज हवा के साथ आसमान में छाए बादल, कई इलाकों में बिजली गुल

हाथरस में मौसम ने पिछले कई दिन से मौसम का मिजाज रोजाना बदल रहा है। नौतपा के दूसरे दिन इस बार भीषण गर्मी नहीं पड़ी और तापमान में गिरावट देखने को मिली। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह से ही मौसम सुहाना हो गया कि तुलना में दो डिग्री की कमी आई है। कल अधिकतम

तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था। सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। कुछ देर के लिए धूप में निकली लेकिन इसके बाद फिर आसमान में बादल छा गए। परसों रात आई तेज आंधी और बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। तेज हवाओं के कारण हाथरस और देहात में बिजली की लाइंगों में फाल्ट हुए हैं बिजली गुल होने से लोगों

चंद्रशेखर आजाद का हाथरस में स्वागत बोले—राजनीति में भागीदारी जरूरी

आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद आगरा से अलीगढ़ की यात्रा के दौरान हाथरस पहुंचे। ऐसी पॉलिटेक्निक के समाने कप्तान सिंह के निवास पर पार्टी कार्यकार्ताओं ने उनका जा शीला स्वागत किया। अन्य कई स्थानों पर भी उनका जोशीला स्वागत किया गया। चंद्रशेखर आजाद ने मिडिया कर्मियों से बातचीत में बताया कि पार्टी मंडल स्तर पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी विस्तरीय पंचायत सुनाव और विधानसभा सुनाव की तैयारियों में जुटी है। उन्होंने समाज की स्थिति पर

चर्चा करते हुए कहा कि 2007 से 2012 तक समाज का राजकाज रहा। 2027 में इसे 15 साल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि राजकाज से दूर रहने वाले समाज को कई तरह की परेशानियों और शोषण का सामना करना पड़ता है। हमारा समाज को भी तरह-तरह की पाबन्दियां और शोषण का समाना करना पड़ रहा है। आजाद ने कहा कि पहले समाज के लोग भोले-भाले थे, जिनका शोषण किया जाता था। पार्टी दौरान कुछ लोगों ने अपनी समस्याएं भी रखीं, जिन पर सांसद ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस समाज पार्टी लगातार संघर्ष... अब आजाद ने कहा कि समाज राजनीतिक शक्ति

भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सादाबाद में अंबेडकर पार्क का दौरा किया

भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सादाबाद में अंबेडकर पार्क का दौरा किया। उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर को माल्यार्पण किया और समर्थकों को संबोधित किया। चंद्रशेखर ने सिकंदराराज सत्संग हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि यदि क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज होता तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने जनता

से अपील की कि वे धार्मिक नारों से के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सादाबाद में अंबेडकर पार्क का दौरा किया। उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर को माल्यार्पण किया और समर्थकों को संबोधित किया। चंद्रशेखर ने सिकंदराराज सत्संग हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान में रोटी, रोजगार, अस्पताल और शिक्षा जैसे मूलभूत मुद्दों की बजाय धार्मिक मुद्दों को प्राथमिकता दी जा रही है। महंगाई पर का आवश्यकता है। आने वाले समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षा और संगठन की ताकत जरूरी है। महंगाई इतनी होगी कि सरकार जनता

अलीगढ़

मार्ग मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 3300 करोड़ की बहुआयामी योजनाओं का किया गया लोकार्पण एवं शिलाब्यास
मुख्यमंत्री जी ने बेसिक शिक्षा विभाग की अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ एवं लोकार्पण किया

जल्द होगा नगर निगम कर्मचारी कल्याण संघ का चुनाव— वर्तमान अध्यक्ष महामंत्री ने नगर आयुक्त को चुनाव कराने के लिए सौपा ज्ञापननगर निगम कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष संजय सक्सेना और महामंत्री मानवेंद्र सिंह बघेल नेसा। मवार को नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के समक्ष नगर निगम कर्मचारी कल्याण संघ का 2 वर्षीय चुनाव जल्द कराए जाने का अनुरोध किया। वर्तमान अध्यक्ष और महामंत्री ने नगर आयुक्त को चुनाव की तिथि जल्द घोषित करने संबंधी ज्ञापन भी सौपा। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने वर्तमान अध्यक्ष और महामंत्री को कर्मचारियों के हितों में कार्य करने की अपील करते हुए आगामी बकरीद के उपरांत निर्वाचन तिथि घोषित करने का आश्वासन दिया।

अलीगढ़ मा० मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम मानते हुए बेसिक शिक्षा को भविष्य की ठोस बुनियाद बनाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को लोक भवन, लखनऊ में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने बेसिक शिक्षा विभाग की अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ एवं लोक पर्ण किया। इस अवसर पर निपुण प्लस एप के माध्यम से शनिपुण प्लस स्पॉट अस. 'समेट योजनाश की शुरुआत की गई जो कक्षा 3 से 12 तक के विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के मूल्यांकन की एक सशक्त पहल है। इस योजना से विद्यार्थियों की विषयवस्तु की समझ का आकलन कर उनकी जरूरतों के अनुसार शैक्षणिक सहयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह पहल शिक्षा की गुणवत्ता में एक महत्वपूर्ण मील का पथर सिद्ध होगी। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर, अलीगढ़ में जिले के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों व शिक्षकों की उपस्थिति में किया गया। मुख्यमंत्री जी ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए दो जोड़ी, यूनिफॉर्म, जूतेमोजे, स्कूल बैग, स्केटर एवं स्टेशनरी के लिए अभिभावकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रति छात्र 1200 रुपये की धनराशि स्थानांतरित की। इसके साथ ही प्रदेश भर में 3300 करोड़ की धनराशि के विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्याय किया गया जिसमें स्थापित 43 मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय एवं 66 अभ्युदय विद्यालयों का शिलान्यास एवं उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नवनिर्मित भवनों एवं छात्रावासों का लोकार्पण किया गया। शिक्षा के डिजिटलीकरण को गति देते हुए मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान में एजुकेशनल ब्रॉडका. स्टिंग स्टूडियो, 5258 विद्यालयों में आईस. एटीसी लैब, 503 पीएम श्री विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी और 7409 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में शिक्षा क्षेत्र में निपुण आकलन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 51667 शिक्षकों का सम्मान किया गया एवं उन्हें टैबलेट भी वितरित किए गए। साथ ही शैक्षिक पुस्तक श्वसारथीश एवं श्वशनुरूपणश का विमा.



‘चन किया गया। ओनजीसी को सीएसआर फंड से 150 करोड़ की धनराशि से 05 मॉडल कम्पोजिट विद्यालय के लिए सम्मा. नित किया गया प्रदेश के मा० गन्ना विकास एवं चीनी मिलों और जनपद प्रभारी मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारतवर्ष दुनियां की सबसे प्राचीन शिक्षा की पाठशाला रही है। जब दुनियां को खानपान का भी ज्ञान नहीं थी तब हमारे देश में वेद और बाल्मीकि रामायण लिखी गई। पाटि. लिपुत्र विश्वविद्यालय में देश-विदेश के छात्र पढ़ने आते थे, तब भारत विश्वगुरु था। 1000 सालों के मध्य शिक्षा का पतन हुआ, हमारे विश्वविद्यालयों में आग लगाई गई और आक्रांताओं ने अपनी शिक्षा और भाषा को थोपने का प्रयास किया। आज प्रतिस्पर्धा का युग है और हमें शिक्षा को पुनः उसी सम्मान की ओर लेकर जाना है। अब अध्यापक समय से विद्यालय पहुँच रहे हैं। परिषदीय विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ी है, डीबीटी के माध्यम से उन्हें छात्रवृत्ति एवं यूनिफर्म के लिए धनराशि प्राप्त हो रही है। मा० प्रभारी मंत्री जी ने बताया कि अलीगढ़ में 30 करोड़ की धनराशि से अत. रौली के गणियावली में मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय, 1.40 करोड़ से बहराबद में मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय बनाया जाएगा। जिले के 06 कस्तूराबा गांधी विद्यालयों का उच्चीकरण हुआ है कायाकल्प में 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर जिले को प्रदेश में प्रथम स्थान वर्हीं निपुण भारत मिशन में पांचवा स्थान मिला है। जिले के 251 परिषदीय एवं 22 पीएम श्री विद्यालयों मार्ट क्लास का निर्माण कार्य कराया गया है। 13 करोड़ की धनराशि से जिले के सभी शासकीय विद्यालयों में फर्नीचर उपलब्ध कराया जा रही है और

नगर निगम के सहयोग से 03 करोड़ की धनराशि से एलमपुर में स्मार्ट स्कूल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा किए गए लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रमों से शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आएगा और बेसिक शिक्षा की तसवीर बदलजाएगीकार्यक्रम में मा० मुत्री जी द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में समर कैप के उत्कृष्ट संचालन के लिए 26 अनुदेशक एवं शिक्षामित्र, निपुण आकलन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 26 शिक्षकों, स्मार्ट क्लास के उत्कृष्ट संचालन के लिए 13 शिक्षकों एवं अलीगढ़ महत्सव में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 24 शिक्षकों एवं शिक्षणेत्र कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इससे पूर्व मा० प्रभारी मंत्री जी ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मॉ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कस्तूरबा गँधी बालिका विद्यालय धनीपुर की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर मा० सांसद श्री अनूप प्रधान, विधायक बरौली ठा० जयवीर सिंह, मा० विधायक कोले श्री अनिल पाराशर, मा० विधायक छर्रा ठा० रवेन्द्रपाल सिंह, मा० विधायक इगलास श्री राजकुमार सहयोगी, मा० एमएलसी डा० मानवेन्द्र प्रताप सिंह, प्रो० तारिक मसूर, चौधरी ऋषिपाल सिंह, मा० अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती विजय सिंह, जिलाध्यक्ष श्री कृष्णपाल सिंह, महानगर अध्यक्ष इंजी० राजीव शर्मा, जिला महामंत्री श्री शि. वनारायण शर्मा, जिलाधिकारी संजीव रंजन, एसएसपी संजीव सुमन, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा, सीडीओ प्रखर कुमार सिंह, एडीएम वित्त प्रमोद कुमार, बीएसए राकेश कुमार सिंह समेत अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।

माझे प्रभारी मंत्री ने आपदा राहत के तहत तीन परिवारों को प्रदान किए 08 लाख 05 हजार की धनराशि के चौक

अलागढ़ रु उत्तर प्रदेश सरकार के मा० गन्ना विकास एवं चीनी मिलें और जनपद प्रभारी मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने सोमवार को कल्याण सिंह हैबीटेट सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में जिले में दैवीय आपदा जैसे कि आंधी, तूफान, वर्षा एवं ओलावृष्टि से प्रभावित परिवारों से भेट कर उन्हें ढांडस बंधाया और आर्थिक सहायता स्वरूप मुआवजा राशि के चेक वितरित किए। मा० मंत्री जी द्वारा आपदा से प्रभावित दो परिवारों को चारचार लाख रुपये तथा एक परिवार को पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता के चेक प्रदान किए गए। यह सहायता राज्य सरकार की आपदा राहत नीति के अंतर्गत अनुमन्य धन। राशि के अनुसार दी गई है। इस अवसर पर मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार हर संकट की घड़ी में आमजन के साथ खड़ी है। सरकार की मंशा है कि किसी भी आपदा के समय पीड़ितों को तत्काल राहत पहुँचे, जिससे उन्हें अपने



जीवन को पुनः व्यपरित करने में सहायता मिल सके। उन्होंने एडीए वित एवं प्रभारी अधिकारी आपदा प्रमोट कुमार को निर्देशित किया कि शेष प्रभावितों को भी शीघ्र सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए और राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथि थलता न बरती जाए। कार्यक्रम में माठ मंत्री जी द्वारा आपदा राहत के तहत श्रीमती राकेश शर्मा पत्नी रमेश चन्द्र, बावरी मण्डी कोल एवं श्रीमती रिकी पत्नी सत्यपाल गहतोली गंग हारूनपुर कलां अतरौली को 0404 लाख रुपये एवं श्रीमती ममता देवी पत्नी राहुल मादक टप्पल खेर को 05 हजार रुपये के चौक प्रदान किए गए।

अलीगढ़ में बेहतर कानून व्यवस्था और अपराध मुक्त माहौल बनाए रखने के लिए थाना प्रभारियों और सब इंस्पेक्टरों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया

卷之三

पीगढ़ में बेहतर कानून व्यवस्था और अराध मुक्त माहौल बनाए रखने के लिए ना प्रभारियों और सब इंस्पेक्टरों के यथेत्र में बदलाव किया गया है। एसपी संजीव सुमन ने फेरबदल करते सभी को तत्काल चार्ज लेने के निर्देश दी किए हैं। अतरौली थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विजयकांत के गाजियाबाद ट्रांसफर बाद कई थानों में फेरबदल किया गया महुआखेड़ा थाना प्रभारी सत्यवीर सिंह अतरौली थाना प्रभारी बनाया गया है। रौली में तैनात इंस्पेक्टर क्राइम जोगेंद्र ह को महुआखेड़ा थाना प्रभारी बनाया गया है। थाना एचटीयू में तैनात इंस्पेक्टर यधान सिंह को पिसावा थाना प्रभारी बनाया गया है। क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर

पेक्टर सरिता द्विवेदी को गोधा थाना प्रभारी से बनाया गया है। वहीं पिसावा थानाध्यक्ष के एसआई रंजीत कुमार को एसओ गोरड़ से बनाया गया है। इन सब इंस्पेक्टरों के बदले थानेथाना प्रभारियों के साथ ही १५ सब इंस्पेक्टरों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया गया है। इसमें लाइन हाजिर चल रहे एसआई नारायण दत्त तिवारी को चौर्की प्रभारी सासनीगेट बनाया गया है। एसआइ अमित कुमार को थाना अकराबाद से चौर्की प्रभारी पनेठी बनाया गया है। लाइन हाजिर चल रहे एसआई मनिंद्र सिंह को चौर्की प्रभारी खेरेश्वर, बद्रीराम को चौकी प्रभारी से बहादुरपुर, प्रमोद वशिष्ठ को थाना गंगारीसे चौकी प्रभारी रायपुर थाना अतरौलीसे अरुण कुमार को चौकी प्रभारी गोंडा, योरोंट्रोपी

कुमार को पुलिस लाइन से चासैकी प्रभारी नगला पटवारी, एसआई उपेंद्र कुमार को विशेष जांच प्रकोष्ठ से एंटी थैफट टीम और बतन सिंह को पुलिस लाइन से विशेष जांच प्रकोष्ठ में भेजा गया है। जनसुनवाई की शिकायतों तत्काल हो दूरएसएसपी से सभी पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए हैं कि थाने में आने वाली शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया जाए। आमजनों के काम में बिल्कुल भी लापरवाही न की जाए। अगर आमजनों के काम में किसी तरह की लापरवाही मिली और शिकायत आई तो संबंधित पुलिस कर्मी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

**जल्द पेयजलापूति में दिखेगा सुधार—ऊपरी
तह के पानी को अलीगढ़ में लाने के लिए
नगर आयुक्त ने शुरू की कवायद**

U

पेयजल किल्लत वाले क्षेत्र में जल्द खुदगे एक्स्ट्रा बोरवेल-पम्प सेट किये जायेंगे अपग्रेड-पेयजल टैंकर व पेयजलापूर्ति के संसाधनों का होगा भौतिक सत्यापनरू-नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणापेयजल की किल्लत वाले क्षेत्र में जल्द पेयजलापूर्ति बनेगी प्रभावी-नगर आयुक्त ने 90 पार्षद वार्ड वाइज पेयजलापूर्ति का तलब किया ब्लौराबढ़ती गर्मी में शहर के कई क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति की किल्लत को दूर करने के लिए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने जलकल विभाग के साथ समीक्षा करते हुए अधिनस्थों से नगर निगम के सभी 90 पार्षद वार्ड की आबादी, वार्ड में पेयजल की खपत, की जा रही पेयजलापूर्ति और अतिरिक्त पेयजलापूर्ति की आवश्यकता का पूरा ब्यौरा तलब किया है। नगर आयुक्त ने पेयजल की किल्लत वाले क्षेत्रों में अति-रिक्त बोरवेल खुदवाए जाने के लिए सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को कल्याण सिंह हैंडिटेक सेंटर में पेयजल की किल्लत वाले मोहल्लों में पेयजलापूर्ति को कैसे प्रभावी बनाया जाए इसको लेकर नगर आयुक्त ने जलकल विभाग के प्रभारी महाप्रबंधक जल, सहायक अभियंता व अवर अभियंता के साथ समीक्षा की। नगर आयुक्त ने अलीगढ़ में गिरते जमीनी जलस्तर पर विता जाहार करते हुए आवश्यकों का निर्देश दिए कि अलीगढ़ में अब ग्राउंडवाटर धीरे-धीरे नीचे जा रहा है अलीगढ़ नगर निगम को आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऊपरी तह के पानी (सरफेस वाटर) पर काम करने की जरूरत है। नगर आयुक्त ने जल जीवन मिशन शहरी योजना के तहत बुलंदशहर से आ रही जवां नहर के पानी को शहर वासियों के लिए सरफेस वाटर के रूप में नगर निगम सीमा में लाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश प्रभारी महाप्रबंधक जल सुरेश चंद को दिए। नगर आयुक्त ने पेयजल की किल्लत वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता पर अति-रिक्त बोरवेल लगाए जाने के लिए तत्काल सर्वे करने, सभी ट्यूबवेल के पंप को अपग्रेड करने और जलकल विभाग की सभी वाहनों, पेयजल टैंकर, मशीनरी का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने 6 दिनों से सासनी गेट ट्यूबवेल की मोटर फूंकने के कारण आपूर्ति न होने, गोपालपुरी में पानी नहीं पहुँचने, पाइप लाइन फटने से जीटी रोड पर जल भराव होने, वार्ड 9 गोपी मिल कंपाउंड में 150 घरों में पानी नहीं पहुँचने, वार्ड 9 नौरगांवाद में जल संकट, वार्ड 36 में पाइप लाइन बिछाने के बावजूद पानी की सप्लाई न होने व मोहल्ले में 70 हैंडपंप के खराब हान, वार्ड 64 फरदास नगर में पानी का किल्लत, वार्ड 35 महफूज नगर के नमन कॉलोनी संकल्प विहार वसुंधरा कॉलोनी अयोध्यापुरी ढोलक बस्ती सरदार बस्ती जाटव बस्ती यादव बस्ती मेघ विहार कॉलोनी जामिया मस्जिद जुबैदा मस्जिद एक नंबर से चार नंबर वाली गली में पेयजलापूर्ति न होने, वार्ड 3 पला रोड कबीर नगर में संत शरण माहौर वाली गली में पेयजल संकट व वार्ड 15 के नगला मसानी पश्च अस्पताल निरंजनपुरी गौशाला गूलर रोड गली नंबर-1 में पानी की किल्लत जैसी कई महत्वपूर्ण समस्याओं पर भी समीक्षा की बैठक में नागरिकों की पेयजल समस्याओं पर तत्काल एक्शन लेने के लिए नगर निगम इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में संचालित कॉल सेंटर नंबर 1533 की निगरानी करने के निर्देश दिए। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा बढ़ती हुई गर्मी और गिरते हुए ग्राउंडवाटर में पेयजलापूर्ति को प्रभावी बनाए जाना एक चौलेंज है और इस चौलेंज को पूरी शिद्दत के साथ नगर निगम शहर वासियों के सहयोग से हासिल करेगा। नगर निगम सीमा में गिरता हुआ भूमिगत जलस्तर एक चिंता का विषय है जवां नहर से सरफेस वाटर को अलीगढ़ में लाने के लिए कवायद को शुरू किया जा रहा है।

जल्द होगा नगर निगम कर्मचारी कल्याण संघ का चुनाव— वर्तमान अध्यक्ष महामंत्री ने नगर आयुक्त को चुनाव कराने के लिए सौपा ज्ञापननगर निगम कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष संजय सक्सेना और महामंत्री मानवेंद्र सिंह बघेल नेसा।
‘मवार को नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के समक्ष नगर निगम कर्मचारी कल्याण संघ का 2 वर्षीय चुनाव जल्द कराए जाने का अनुरोध किया। वर्तमान अध्यक्ष और महामंत्री ने नगर आयुक्त को चुनाव की तिथि जल्द घोषित करने संबंधी ज्ञापन भी सौपा। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने वर्तमान अध्यक्ष और महामंत्री को कर्मचारियों के हितों में कार्य करने की अपील करते हुए आगामी बकरीद के उपरांत निर्वाचन तिथि घोषित करने का आश्वासन दिया।

न्यायपालिका से सवाल, लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद की परंपरा का परिचय और प्रमाण

पिछले दिनों राष्ट्रपति द्वारा पदी मुर्मु ने उच्चतम न्यायालय से 14 सवाल पूछे। ये सवाल राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत किए गए हैं। मूलतरूप ये प्रश्न न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपा. लिका की संवैधानिक शक्तियों और कार्यक्षेत्र से भी संबंधित हैं। राष्ट्रपति ने कानून निर्माण के संबंध में राज्यपाल और राष्ट्रपति को संविधानप्रदत्त शक्तियों को न्यायिक आदेश द्वारा सीमितधनियंत्रित किए जाने पर प्रश्न चिह्न लगाया है। ये प्रश्न भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतर्निहित संवाद की स्वस्थ परंपरा का परिचय और प्रमाण हैं। दरअसल हाल में उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल बनाम तमिलनाडु राज्य नामक वाद का निर्णय दिया था। यह मामला तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों से संबंधित था। राज्य सरकार का कहना था कि विधानसभा द्वारा पारित कई विधेयक लंबे समय से राज्यपाल द्वारा लंबित रखे गए हैं। साथ ही राज्य सरकार ने राज्यपाल द्वारा एक साथ कई विधेयकों को राष्ट्रपति को विचारार्थ भेजने पर भी प्रश्न उठाया था। निश्चय ही, राज्यपाल द्वारा अनिश्चित अवधि तक विधेयकों को लंबित रखना भी संविधानसम्मत नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त मामले में कुछ संवैधानिक पहलुओं को नए सिरे से प्रस्तुत किया है। पहला, राज्यपाल एवं राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए समयसीमा का निश्चित किया जाना है। यह समय सीमा तीन माह तय की गई है। दूसरा, अगर समयसीमा के भीतर राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है तो राज्य के अनुरोध पर उच्चतम न्यायालय 'परमादेश रिट' के तहत विधेयक को स्वीकृति प्रदान करने की क्षमता रखता है। तीसरा, उच्चतम न्यायालय ने स्वयं को संविधान के अनुच्छेद 142 द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हए 10 लंबित विधेयकों को कानून का दर्जा दे दिया है। इस तरह यह पहला अवसर है जब बिना राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति के विधेयक कानून बन गए हैं। यह न्यायपालिका द्वारा अपनी संवैधानिक शक्तियों और मर्यादा का अतिक्रमण है। इस निर्णय की पृष्ठभूमि में संवैधानिक वस्तुस्थिति को समझना आवश्यक है। सर्वप्रथम अनुच्छेद 200 की बात आती है। इसके तहत राज्यपाल या विधेयक को स्वीकृति देता है या उसे रोक लेता है या वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए प्रेषित कर देता है। राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित विधेयक के लिए एक कसौटी का उल्लेख है। वह यह है कि राज्यपाल की राय में यदि वह (विधेयक) कानून बन जाए तो उच्च न्यायालय की शक्तियों को इस प्रकार अत्यधिकृत करेगा कि वह व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी, जिसे भरने के लिए संविधान द्वारा उसका निर्माण किया गया है। 'राज्यपाल की राय में' के दो अर्थ हो सकते हैं। पहला यह कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सहयोग एवं सुझाव से ऐसा करेगा। अब सवाल यह उठता है कि मंत्रिपरिषद जो विधानमंडल का हिस्सा है और विधेयक बनाने में शामिल है, आखिर क्यों पहले अपने क्षेत्राधिकार से बाहर विधेयक पारित करेगी और फिर राज्यपाल को परामर्श देकर उसे राष्ट्रपति को भिजवाएगीदूसरा यह कि राज्यपाल अपने 'विवेकाधिकार' का प्रयोग करते हुए ऐसा करेगा। अनुच्छेद 201 दूसरा अनुच्छेद है, जो इस बहस में आया है। इसमें राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित विधेयक से संबंधित चर्चा है। इसके तहत राष्ट्रपति या विधेयक पर स्वीकृति देता है या उसे रोक देता है। साथ ही वह अपने सुझावों और निर्देश के साथ विधेयक को राज्यपाल के माध्यम से वापस विधानमंडल को भेज सकता है। तत्पश्चात वह पुनरु विधानमंडल से पारित कराकर राष्ट्रपति की

स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसके आगे राष्ट्रपति उस विधेयक पर क्या फैसला लेते हैं? इस पर संविधान में स्पष्टता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार राज्यपाल अब पहली प्रस्तुति में तीन महीने एवं दूसरी प्रस्तुति में अधिकतम एक महीने तक ही विधेयक को अपने पास रख सकते हैं। विधेयक निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल के 'विवेकाधिकार' को उच्चतम न्यायालय ने अब न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत बताया है। यह पहले से चली आ रही प्रणाली में बहुत बड़ा बदलाव है। जिसमें राज्यपाल के विवेकाधिकार को सीमित किया गया है। इसके आगे कोर्ट ने अनुच्छेद 200 एवं 201 के तहत राष्ट्रपति के विचारार्थ प्रेषित विधेयकों को संवैधानिक एवं वैधानिक त्रुटियों से बचाने के लिए राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से सुझाव लेने के लिए भी निर्देशित किया है। राष्ट्रपति को दिए गए निर्देश के मद्देनजर ऐसा प्रतीत होता है कि विधेयक के कानून बनने के पूर्व ही न्यायालिका का हस्तक्षेप हो रहा है। किसी भी विधेयक को प्रस्तुत करने एवं उस पर बहस करने का कार्य जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का ही होता है। विधायिका के इस कार्य में हस्तक्षेप संविधान के बुनियादी ढांचे को चुनौती देता है। भारत संघीय व्यवस्था के बावजूद केंद्रीय प्रवृत्ति वाला राष्ट्र है। यह व्यवस्था अलगाव और अराजकता को नियंत्रित करते हुए देश की एकता-अखंडता सुनिश्चित करती है। उपरोक्त निर्णय की पृष्ठभूमि में राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आलोक में न्यायालिका, विधायिका और कार्यपालिका के संबंध और कार्यक्षेत्र भी पुनर्परिभाषित होंगे।

उद्देश्य से भटकी भारत की राजनीति, समाज को जागरूक—

सचेत करने का काम भुला दिया जाना चिंताजनक

राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चुनावीतों के इस संवेदनशील समय में भी दलतंत्र के बीच राष्ट्रीय प्रश्नों पर एकता नहीं है। आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। राजनीति के माध्यम से समाज को जगाकर राष्ट्रीय भाव भरने का काम प्रायः बंद है। राजनीति का उद्देश्य वोट बैंक जुटाना ही दिखाई पड़ रहा है। अजीब स्थिति है। आमजनों में राष्ट्रभक्ति का ज्वार है, लेकिन दलतंत्र में राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर भी सहमति नहीं है। यह तब है जब भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान की असलियत बताने के लिए दुनिया के प्रमुख देश जा रहे हैं। इस पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। इससे वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य नि. राशा पैदा करने का काम कर रहा है। याद रहे कि राजनीति ही सारी समस्याओं का समाधान नहीं होती। समय—समय पर सामाजिक पुनर्जागरण भी अनिवार्य होते हैं। सचेत राष्ट्रभक्ति शाश्वत मूल्यों और आदर्शों के लिए जागरूकता पैदा करते रहे हैं। भारत की संस्कृति और राष्ट्रभाव का विकास इसी निरंतरता में हुआ है। विस्तुतः कोई भी समाज व्यवस्था स्वयं पूर्ण नहीं होती और न ही राजनीति। संस्कृति राष्ट्रभाव का संवर्धन करती है और संविधान राजव्यवस्था का मार्गदर्शी होता है। विश्व के सभी समाजों में अंतर्विरोध रहे हैं और आज भी हैं। यूरोपीय समाज में एक समय घोर अंधकार था। अंधविश्वास जोर पर था। सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने 13वीं सदी से पुनर्जागरण का काम लंबे समय तक जारी रखा। पुनर्जागरण से यूरोपीय समाज और दृष्टिकोण में आधारभूत परिवर्तन आए थे। भारत का स्वाधीनता संग्राम अपने ढांग का दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन था। यह संघर्ष लंबा चला था। सत्ता परिवर्तन ही इस आंदोलन का लक्ष्य नहीं था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लाखों लोगों का उत्पीड़न हुआ था। लेखक—विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता उत्पीड़ित किए गए। तब सत्ता प्राप्ति की प्रबल आशा नहीं थी, लेकिन आंदोलन राष्ट्रीय स्वामिनान्, स्वदेशी और स्वराष्ट्र भाव से जड़ा था। गांधी जी ने कहा था, 'हम ब्रिटेश सत्ता को हटाने के लिए ही आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हम अंग्रेजी उपकरणों से देश नहीं चला सकते। इससे तो अंग्रेजी सत्ता ही भली है।' रा. जनीतिक सत्ता की शक्ति बेशक बड़ी होती है, लेकिन सत्ता के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का काम संभव नहीं है। राजनीति का असीम है। गांधी जी ने कहा था, 'सत्ता परिवर्तन ही हमारा उद्देश्य नहीं है। हम राष्ट्रजीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन चाहते हैं।' डा. आंबेडकर सत्ता सहित सभी लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन वोट के लिए किसी भी सीमा तक जाना चिंताजनक है। राष्ट्रजीवन के आदर्शों एवं निहित स्वार्थी मूल्यों में टकराव स्वाभाविक है। सजग राष्ट्रभक्ति इतिहास से सीख ले रही है। राष्ट्रहित में समाज को जागरूक करते हैं। जो समाज ऐसा नहीं करते, वे जड़ हो जाते हैं और जो ऐसा करते हैं वे इतिहास के मार्गनिर्माता कहे जाते हैं। राष्ट्रजीवन के अनेक मुद्दे जनअभियान से ही हल किए जा सकते हैं। दलतंत्र से ऐसी समस्याओं के समाधान की अपेक्षा नहीं की जा सकती। सभी दलों को मिलकर जातिवाद, संप्रदायवाद आदि के विरुद्ध अभियान चलाने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जिन समस्याओं का समाधान राजनीति नहीं कर सकती, उनका सजग और एकजुट समाज कर सकता है। बर्तात राजनीतिक दल समाज को सजग करें। समाज को जागरूक करने और उसमें उसके कर्तव्य के निर्वहन का भाव जगाने का अभियान चलाकर हर तरह की समस्याओं का आसानी से समाधान संभव है, मगर आज की राजनीति सामाजिक जागरूकता लाने का कोई ठोस जतन नहीं करती। राजनीतिक क्षेत्र में मूल्यों का अवमूल्यन हुआ है, लोकहित की तुलना में निजी एवं दलहित सर्वोपरि हो गया है। केवल वोट हितैषी राजनीति से सामाजिक परिवर्तन का काम सही तरह संभव नहीं है। सामाजिक जागरण का काम सतत प्रवाही होना चाहिए और यह काम राजनीति के दलों को करना चाहिए। यदि जन जागरण का काम रुकता है तो दुर्गति शुरू हो जाती है। और लोकतंत्र की

ईडी की विश्वसनीयता

यह कोई नई बात नहीं है कि देश की जांच एजेंसियों पर सरकार की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करने को लेकर विपक्षी राजनीतिक दलों की तरफ से पक्षपात के आरोप लगे हैं। सरकारी जांच एजेंसियों को वे विपक्ष के नेताओं को डाराने-धमकाने का हथियार बताते रहे हैं। अब इन्हीं चिंताओं और सवालों पर देश की शीर्ष अदालत ने भी मोहर लगाई है। विपक्षी नेता खासकर धनशोधन निरोधक अधिनियम के तहत की जा रही कार्रवाइयों पर रोक लगाने की गुहार लगाते रहे हैं। उनका आरोप रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय सरकार के हितों की पूर्ति के लिये दुराग्रह से कार्रवाई करता है। हालांकि, अदालत का मानना रहा है कि प्रष्टाचार, देशविरोधी गतिविधियों तथा आतंकवादी संगठनों को मदद पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई अतार्किक नहीं है। सवाल इस बात को लेकर भी उठते रहे हैं जिनमें आरोप पत्र ईडी द्वारा दायर किए जाते हैं, उसकी तुलना में दोषसिद्धि की संख्या में बेहद ज्यादा अंतर क्यों है। जो इस बात की ओर इशारा करता है कि मामले दुराग्रह पहलगाम हमले के बाद भारत की कूटनीति के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों की यात्रा कर रहा है। भारत दुनिया को अपना संदेश स्पष्ट रूप से पहुंचाना चाहता है, जिसके लिए अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से दिया, लेकिन इतना काफी नहीं था। नई दिल्ली की सुरक्षा चिंताओं और आतंकवाद को लेकर उसकी बदली रणनीति से वाकिफ कराने व पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए भारत का सर्वदलीय प्रति. निधिमंडल इस समय विभिन्न देशों की यात्रा पर निकला हुआ है। इन डेलिगेट्स को भारत का संदेश स्टीक और साफ से प्रेरित होते हैं। अदालत भी मानती है कि ठोस प्रमाण के बिना किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक हालिया मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाइयों पर कोर्ट ने उसे कड़ी फटकार लगाते हुए सीमाएं लांघकर संघीय ढांचे के अतिक्रमण करने की बात कही है। कोर्ट ने यह टिप्पणी तमिलनाडु में शराब की दुकानों के लाइसेंस देने में बरती गई कथित धांधली में राज्य विपणन निगम के विरुद्ध धनशोधन मामले में ईडी की जांच पर की है। दरअसल, निगम द्वारा शीर्ष अदालत में मामला ले जाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने न केवल जांच रोकी बल्कि ईडी की कार्रवाइयों पर सख्त टिप्पणियां भी की हैं। निस्संदेह, ईडी को इस सुप्रीम नसीहत पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। कोर्ट को यहां तक कहना पड़ा कि प्रवर्तन निदेशालय संघीय अवधारणा का उल्लंघन कर रहा है। उल्लेखनीय है कि पीएमएलए की धाराओं के दुरुपयोग को लेकर शीर्ष अदालत पहले भी ईडी के खिलाफ सख्त टिप्पणी कर चुकी है। निसंदेह, अदालत की इस सख्त टिप्पणी से अंदाज में पूरे विश्व तक पहुंचाना है ताकि पाकिस्तान को प्रोपर्गेंडा का मौका न मिले। कूटनीति की भाषारू कूटनीति में हर शब्द मायने रखते हैं। यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस भाषा में बात रखी जा रही है। ऐसे में जब भारतीय प्रतिनिधिमंडल को दुनिया के हर कोने में जाना है, तब तो और भी अहम हो जाता है कि उनकी आपस की बातों में कोई टकराव या विरोधाभास न हो। मेसेज इस तरह दिया जाए कि सभी उसे एक ही तरह से समझें और इसके लिए अंग्रेजी से बेहतर माध्यम कोई नहीं। भारत इस मामले में खुद पर गुमान कर सकता है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक उसकी लगभग 10% आबादी अंग्रेजी बोलती है। अगर उन्हें भी शामिल कर लिया जाए, जो अंग्रेजी बोल

उन तमाम विपक्षी दलों को संबल मिलेगा जो आए दिन इंडी व अन्य जांच एजेंसियों का सत्तापक्ष द्वारा दुरुपयोग करने का आरोप लगाते थे। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु राज्य विपणन निगम की दलील थी कि जिन शराब की दुकानों के लाइसेंस देने में अनियमितताओं के मामले में इंडी ने हस्तक्षेप किया है, उसमें वर्ष 2014 से कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इस मामले में चालीस से अधिक प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं। वहीं निगम कई मामलों में शिकायतकर्ता है। ऐसे में इस मामले में इंडी के कूदने पर सवाल उठे हैं। यहीं वजह है कि कोर्ट ने इंडी की इस जांच पर रोक लगा दी है। उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु सरकार भी इंडी की कार्रवाई को सम्बोधित अधिकारों व संघीय ढांचों का उल्लंघन बताती रही है। विश्वास किया जाना चाहिए कि कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद इंडी केंद्र की इच्छाओं के अनुरूप आंख बंद कर कार्रवाई करने की बजाय अपनी कार्यशैली में अपेक्षित परिवर्तन करेगी।

नहीं सकते, लेकिन पढ़ और समझ सकते हैं तो यह आंकड़ा दोगुना हो जाता है। अंग्रेजी पर पकड़ रखने वाली इतनी बड़ी आबादी किसी और देश के पास नहीं। यह भाषा की ताकत है और इसी के बूते हिंदुस्तान के प्रफेशनल्स अमेरिका से लेकर यूरोप तक अपना दबदबा बनाए हुए हैं सिखाई जाए अंग्रेजीरु भाषा संवाद का जरिया भर नहीं, पहचान भी है। लेकिन यह भी सच है कि किसी देश की पहचान केवल उसकी भाषा तक सिमटी नहीं होती। भारत को अपनी अधिक से अधिक आबादी को अंग्रेजी सिखाने पर जोर देना चाहिए और इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि इससे भारतीयता कम हो जाएगी।

SPARSH PUBLIC SCHOOL

An English Medium School

Admission Open

2025-2026

1-:Activity Rooms

2 - : Clean and Hygienic Toilets

3 -: Clean Drinking Water

4 - : Safe and Secure Environment

5- : Classrooms

6- : Health Unit

**5/467 - A Hari Vilas Nagar
I.T.I Road, Aligarh**

M :- sparshpublicschool@gmail.com

+91 9837889535

+91 9045166719